प्रकाशन का 46 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 46 अंक – 46 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी. /93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 29 – 06 दिसम्बर 2021 मूल्य पांच रुपए

क्या चार शून्य का परिणाम नड्डा के काम की परख के आग्रह का ही एडवांस जबाव है

शिमला/शैल। उप चुनावों के बाद पहली बार अपने घर बिलासपुर आये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने वहां बने एम्स के उद्घाटन के अवसर पर प्रदेश की जनता से आग्रह किया है कि वह जो काम करें उसकी पीठ थपथपायें और जो काम न करें उसे घर बिठायें। इसी के साथ अपने पार्टी के लोगों से भी उन्होंने कहा है कि वह स्ट्रांग लीडर की खोज करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का हिमाचल अपना घर है और वह दो बार यहां मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपने गृह राज्य में ही भाजपा की सरकार होने के बावजूद यदि पार्टी उपचुनाव में सारी सीटें हार जायें तो इस पर राष्ट्रीय स्तर पर तो पहले सवाल उनसे पूछे जायेंगे। शायद इसीलिए उपचुनावों की हार राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की चर्चा बनी। क्योंकि हिमाचल जैसे छोटे से राज्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से हिमाचल की भी पहचान बनी है। नड्डा के अपने लिये भी इस हार के दूरगामी परिणाम होंगे। इन्हीं परिणामों की आहट के कारण ही वह प्रदेश की सरकार को चाहकर भी न तो खुलकर अभयदान दे पा रहे हैं और न ही अनुशासन का चाबुक चला पा रहे हैं।

स्मरणीय है कि विधानसभा की तीनों ही सीटों पर जब उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी तो तीनों ही जगह विरोध और विद्रोह के स्वर मुखर हुये थे। अर्की से गोबिंद राम शर्मा ने तो चुनाव प्रचार के लिए अपनी ड्यूटी ही बाहर लगवा ली थी। फतेहपुर से तो कृपाल परमार को तो मुख्यमंत्री अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर ही ले आये थे। कोटखाई में तो बरागटा ने निर्दलीय होकर चुनाव लड़ भी लिया और पार्टी के उम्मीदवार की तो जमानत तक जब्त हो गयी। बरागटा का टिकट कटने पर ही यह बाहर आया था कि प्रदेश नेतृत्व तो उन्हें टिकट देना चाहता था परंतु हाईकमान ने काट दिया। हिमाचल के संदर्भ में यह हाईकमान नड्डा ही थे और हैं क्योंकि यह उनका अपना गृह राज्य है। तीनों जगह टिकटों के गलत आवंटन का आरोप लगा है और अपरोक्ष में यह आरोप नड्डा पर ही आता है। शायद इसीलिए वह खुलकर

स्पष्ट कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं।

लेकिन अभी एम्स के उद्घाटन के अवसर पर ही जिस तरह से पुलिसकर्मियों के परिजनों ने मौन प्रदर्शन किया है वह नड्डा के लिये एक पर्याप्त संकेत और संदेश हो जाता है कि प्रदेश के कर्मचारीयों ही की क्या दशा है। क्योंकि जेसीसी की बैठक के बाद पहला प्रदर्शन बीएमएस के लोगों ने किया और दूसरा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया। आउटसोर्स पर लगे कर्मचारी अपने लिये एक निश्चित नीति की मांग कर रहे हैं। सरकार के फैसले के कारण जेबीटी प्रशिक्षु और बी एड में टकराव की स्थिति बन चुकी है। इस तरह प्रदेश कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग सरकार से नाराज चल रहा है। यह पूरी तरह सामने आ चुका है।

चुनाव में हार के कारण जानने के लिए हुए मंथन में भी एक राय नहीं बन पायी है। यह रणधीर शर्मा और सुरेश कश्यप के अलग – अलग ब्यानों से सामने आ चुका है। राजीव बिंदल के करीबी पवन गुप्ता ने तो त्यागपत्र देने का सबसे बड़ा कारण ही मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भ्रष्टाचार को संरक्षण देना बताया है। कृपाल परमार ने यहां तक कह दिया कि अब जलालत सहने की सारी हदें पार हो गयी हैं। पार्टी ने भले ही इन त्याग पत्रों पर ज्यादा चर्चा नहीं होने दी है। लेकिन जनता के पास तो यह सब कुछ पहुंच चुका है। बल्कि इसके बाद यहां और मुखरता के साथ चर्चा में आ गया है कि धूमल के करीबियों को इस सरकार में चुन – चुन कर हाशिये पर धकेलने के प्रयास हुये हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर तो जयराम और अनुराग ठाकुर का टकराव तो एक ही मंच पर सामने भी आ चुका

शेष पृष्ठ 8 पर.....

क्या प्रदेश कांग्रेस में अभी से मुख्यमंत्री के लिए रेस शुरू हो गयी है

शिमला/शैल। हिमाचल कांग्रेस के लिए 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद यह 2021 के उप चुनाव जीतना एक बहुत बड़ी जीत है। शायद इतनी जीत की उम्मीद कांग्रेस को भी नहीं थी। इन उपचुनावों में सरकार भाजपा और कांग्रेस सभी के आकलन फेल हुये हैं। यदि कांग्रेस को उम्मीद होती कि वह मंडी का लोकसभा उपचुनाव जीत जायेगी तो शायद प्रतिभा सिंह की जगह कॉल सिंह या सुखराम का पौत्र आश्य शर्मा यहां से उम्मीदवार होते। प्रतिभा सिंह को अर्की से विधानसभा ही लड़नी पड़ती और वह इंकार न कर पाती। यदि राष्ट्रीय स्तर पर बदल रहे राजनीतिक परिदृश्य को पंडित सुखराम थोड़ा सा भी समझ पाते तो अनिल शर्मा 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ही भाजपा और उसकी विधायकी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके होते। यह सब इस समय इसलिए प्रसांगिक है क्योंकि अभी भी सभी पक्षों के नेता गण जन आकलन नहीं कर पा रहे हैं।

कांग्रेस में चारों उपचुनाव जीतने के बाद अभी से अगले मुख्यमंत्री के लिए रेस लग गयी है। इस रेस के संकेत हॉली लॉज में पिछले दिनों हुये आयोजन से उभरने शुरू हो गये हैं। प्रतिभा सिंह की जीत के बाद जिस तरह से कुछ लोग उन्हें जीत की बधाई देने पहुंचे और इस जीत पर जिस तरह से भोज दिया गया तथा कांग्रेस ऑफिस से बाहर पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया उससे यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि वह अब प्रदेश कांग्रेस की धुरी बनने की भूमिका में आ गयी है। इसी से एक वर्ग उन्हें अभी प्रदेश का अध्यक्ष बनाने की योजना में लग गया है। लेकिन यह वर्ग भूल गया है कि जो लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे वह पूरे प्रदेश का नहीं वरन एक क्षेत्र विशेष का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जैसे ही यह संकेत सामने आये की वह प्रदेश कांग्रेस का केंद्र होने कीओर बढ़ रही हैं तभी दिल्ली में उनके शपथ ग्रहण समारोह में सारे बड़े नेता नहीं पहुंचे और वहीं से कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठने शुरू हो गये। प्रतिभा सिंह को वीरभद्र सिंह बनने में समय लगेगा। यह वीरभद्र सिंह ही थे जो अपने विरोधी की योग्यता की भी कदर करते थे। लेकिन उन्ही वीरभद्र सिंह को सुखबिन्द्र सुक्खु को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने के लिये आनंद शर्मा, आशा कुमारी और मुकेश अग्निहोत्री का साथ लेना पड़ा। इसका परिणाम हुआ की कुलदीप राठौर को अध्यक्ष बनाना पड़ा।

लेकिन कुलदीप राठौर को 2019 के लोकसभा चुनाव और इन चुनावों के कारण आये 2 विधानसभा चुनावों में संगठन के सारे बड़े नेताओं का कितना सहयोग मिला वह स्व:वीरभद्र सिंह के उसी ब्यान से स्पष्ट हो जाता है जब उन्होंने यहां तक कह दिया था की मंडी से कोई भी मकर झंडू चुनाव लड़ लेगा। इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों से निकलकर कुलदीप राठौर की प्रधानगी में ही सोलन और पालमपुर की नगर निगमों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। यही जीत अब उपचुनावों में सामने आ गयी। जबकि इसी दौरान राठौर के राजनीतिक संरक्षक माने जाने वाले आनंद शर्मा का नाम कांग्रेस के असंतुष्ट के जी – 23 के ग्रुप का एक बड़ा नाम बनकर सामने आ गया। इस समय कांग्रेस

शेष पृष्ठ 8 पर.....

युवा पीढ़ी को ऐतिहासिक घटनाओं की सही जानकारी उपलब्ध करवाई जानी चाहिएः राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि इतिहास हमारी सभ्यता, संस्कृति और साहित्य का अभिन्न अंग है और यह तथ्यों पर

आधारित होना चाहिए। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। राज्यपाल हमीरपुर के निकट ठाकुर जगदेव चंद ठाकुर स्मृति शोध संस्थान में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 'भारतीय स्वाधीनता आंदोलन: वृत्तांत, स्मृतियां एवं नेपथ्य-नायक' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद एवं वेबीनार के उदघाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। यह दो दिवसीय परिसंवाद भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद और केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के इतिहास विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया।

इस अवसर पर देश भर के विद्वानों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे इतिहास के कई महत्वपूर्ण विषयों को अभी तक स्पर्श ही नहीं किया गया है, ऐसे विषयों पर कई बार हम चर्चा करने से भी डरते हैं। इस दिशा में नेरी में आयोजित यह परिसंवाद निःसंदेह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि ऐतिहासिक घटनाओं की सही डॉक्यूमेंटेशन एवं तथ्यात्मक जानकारी आज की पीढ़ी तक पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने हमारी समृद्ध संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

भारत के इतिहास के संकलन की आवश्यकता पर भी बल देते हुए राज्यपाल ने कहा कि हमारा देश आजादी के बाद ही राष्ट्र नही बना था, बल्कि यह तो हजारों वर्ष से एक राष्ट्र के रूप में अपने पहचान बनाए हुए है।

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश भारतीय इतिहास में कई तरह की भ्रांतियां पैदा हुई हैं, जिनका निवारण करना वर्तमान इतिहासकारों एवं शोधार्थियों की जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि नेरी में आयोजित परिसंवाद में व्यापक अमृत-मंथन के बाद कुछ नया निकलकर आयेगा जोकि देश को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करेगा।

राज्यपाल ने कहा कि आज हमारा देश जहां अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं गोवा भी अपनी मुक्ति का 60वां वर्ष मना रहा है। उन्होंने बताया कि भारत की आजादी के 14 वर्षों के उपरांत गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था। उन्होंने कहा कि गोवा की मुक्ति के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय और अन्य महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनमें उन्होंने जिला कांगड़ा के राम सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गोवा में आज भी लोकसंस्कृति जीवंत है।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने डॉ. ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित एक लघु वृत्तचित्र, डॉ. शिव भारद्वाज की पुस्तक स्वराज संघर्ष में हिमाचल के नेपथ्य नायक, डॉ. ओम प्रकाश शर्मा की पुस्तक इतिहास लेखन में लोक गाथाओं का योगदान और परिसंवाद की स्मारिका का विमोचन भी किया।

भारत के प्रसिद्ध पुरातत्वविद प्रो. बसंत शिंदे ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सलाहकार डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखे। डॉ. कंवरदीप चंद्र ने परिसंवाद की भूमिका पर प्रकाश डाला। संस्थान के निदेशक डॉ. चेतराम गर्ग ने राज्यपाल और अन्य सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा संस्थान की उपलब्धियों की जानकारी दी।

युगपुरूष थे बाबा साहब अम्बेडकरःआर्लेकर

शिमला/शैल। फोरम ऑफ एस. सी एण्ड एस.टी लेजीस्लेटर एण्ड पार्लियामेंटेरियनस तथा डॉ. अम्बेडकर

चैम्बर ऑफ कामर्स-डी.ए.सी.सी के संयुक्त तत्वावधान में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय पांचवें अंतरराष्ट्रीय अम्बेडकर कनक्लेव-2021 के प्रथम सत्र की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की। इस कनक्लेव का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने किया। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में संविधान, शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, स्टार्ट-अप और आर्थिक विकास जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

इस अवसर पर आर्लेकर ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने समता, बन्धुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को तैयार करने का अहम कार्य किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सम्मान और उनके काम को आगे बढ़ाने के जो अभियान चलाये हैं, वे प्रशंसनीय हैं। उन्होंने कहा कि वंचित वर्गो के उत्थान को प्राथमिकता देने के लिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बधाई के पात्र हैं।

हिमाचल के राज्यपाल ने कहा कि बाबा साहब ने समता, करूणा और बंधुता के आदर्शो को, समाज के धरातल पर उतारने का जो लंबा और अहिंसात्मक संघर्ष किया, वह उन्हें एक युगपुरूष का दर्जा दिलाता है। उन्होंने सदियों से अशिक्षा और सामाजिक अन्याय के तले दबे-कुचले लोगों में आशा, आत्म-विश्वास और आत्म-गौरव का संचार किया था। यह प्रसन्नता की बात है कि बाबा साहब के दिखाए आदर्श और मार्ग पर चलकर अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लोगों के लिए फोरम महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

राज्यपाल यूथ होस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नई दिल्ली में यूथ होस्टल्स

एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाईएचएआई की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वाईएचएआई एक वैश्विक युवा संगठन है। उन्होंने कहा कि भारत एक युवा राष्ट्र है और यह हमारा कर्तव्य बनता है कि युवाओं की ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक और रचनात्मक तरीकें से करें।

राज्यपाल को सर्वसम्मति से एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया।

इस अवसर पर उन्होंने देश के विभिन्न भागों से आए वाईएचएआई के सदस्यों द्वारा उन पर विश्वास व्यक्त करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि निर्विरोध चुने जाने पर वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय संगठन का 11 वर्षों से नेतृत्व करने के लिए वाईएचएआई के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शफी पंडित की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सभी बाधाओं के बावजूद एसोसिएशन का मार्गदर्शन किया।

राज्यपाल ने कहा कि गोवा के वन मंत्री रहते हुए उन्होंने गोवा में एक पक्षी महोत्सव का आयोजन किया था। उन्होंने यह जानकारी भी प्राप्त हुई थी कि वाईएचएआई द्वारा प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने वाईएचएआई द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजनों के लिए सराहना करते हुए कहा कि उन्हें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों का भी आयोजन करना चाहिए। उन्होंने नए पदाधिकारियों से अनछुये क्षेत्रों में नए कार्यक्रम संचालित करने का आग्रह किया।

आर्लेकर ने कहा कि संगठन में शक्ति होती है और शक्ति से सफलता हासिल होती है। उन्होंने कहा कि एक साथ संगठित होना शुरुआत है, साथ रहना प्रगति है और एक साथ काम करने से सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि वाइएचएआई को मौजूदा गतिविधियों के अलावा युवाओं को प्रकृति से जोड़ने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा नेतृत्व और प्रकृति दोनों के मध्य सामंजस्य होना अति आवश्यक हैं।

उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमें युवाओं के विचारों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि उनके अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के साथ ही अब उन्हें इस एसोसिएशन को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने सदस्यों से कहा कि शिमला के साथ-साथ दिल्ली और गोवा में भी उनका स्वागत है।

इस अवसर पर, आर्लेकर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. वेंकट नारायणन, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मनोज जौहरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूपेश के. पांडे और अन्य नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया।

प्रदेश ने नवंबर में जीएसटी से 385.21 करोड़ रुपए जुटाए

शिमला/शैल। आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में नवंबर, 2021 में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में 17 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी है और यह 385.21 करोड़ रुपए रहा है, जबकि नवंबर, 2020 में यह कर संग्रह 329.64 करोड़ रुपए रहा था।

उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में नवंबर, 2021 तक सकल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 2815.53 करोड़ रुपए रहा है जोकि गत वित्तीय वर्ष की समान अवधि में 2023.70 करोड़ रुपए था और इस तरह गत वर्ष के मुकाबले जीएसटी संग्रह में अभी तक 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।

उन्होंने कहा कि राज्य के वस्तु एवं सेवा कर में इस वित्तीय वर्ष में निरंतर सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है। वस्तु एवं सेवा कर में यह सकारात्मक बढ़ोतरी दर्ज करने के पीछे करदाताओं की निगरानी, क्षेत्रीय अधिकारियों के प्रदर्शन की निगरानी, विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से अपनी गतिविधियों का संचालन, ई-वे बिलों का भौतिक सत्यापन और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी मुख्य कारक रहे हैं।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

इग्नू ने 15 दिसम्बर तक बढ़ाई पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि

शिमला/शैल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने शैक्षणिक सत्र जुलाई 2021 के लिए विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश (Fresh Admission) की अंतिम तिथि 7 दिसम्बर 2021 तक बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त इग्नू में जनवरी, 2022 सत्र के लिए विभिन्न बैचलर/मास्टर डिग्री कार्यक्रमों में अगले वर्ष/सैमेस्टर में पुनः पंजीकरण (Re-registration) की अंतिम तिथि भी 15 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ा दी गई है।

इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र शिमला के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. जोगिन्दर कुमार यादव ने पीआईबी को बताया कि जनवरी 2021 सत्र में विभिन्न बैचलर डिग्री तथा मास्टर डिग्री (वार्षिक पद्धति) तथा जुलाई 2021 में विभिन्न बैचलर डिग्री तथा मास्टर डिग्री (सेमैस्टर पद्धति) कार्यक्रमों में पहले-से पंजीकृत सभी छात्र पुनः पंजीकरण (Re-registration) के लिए पात्र होंगे।

डॉ. यादव ने बताया कि प्रवेश एवं पुनः पंजीकरण के लिए लिंक इग्नू की वैबसाइट www.ignou.ac.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए इग्नू के किसी भी नजदीकी अध्ययन केन्द्र से या इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, खलीणी, शिमला के दूरभाष संख्या 0177-2624612 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रदेश सरकार श्रमिकों और श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धः जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों और श्रमिक वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए

प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले लगभग चार वर्षो के दौरान दिहाड़ीदारों की न्यूनतम दिहाड़ी को 210 से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति दिन किया है जिससे उनके मासिक मजदूरी में 2700 रुपये की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी प्रदान करना सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी दिहाड़ीदारों को साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने कहा कि उनके परिश्रम और समर्पण के फलस्वरूप ही हिमाचल प्रदेश शत प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में देश का पहला राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षो के दौरान आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,750 रुपये की वृद्धि की है। प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षो के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 2,850 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की है और आज वे प्रतिमाह 7300 रुपये प्राप्त कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड और निगमों की सेवा समिति की नियमित बैठकें आयोजित करवाई जाएगी ताकि कर्मचारियों से संबंधित लंबित मामलों का समाधान किया जा सके। सीमेंट प्लांट प्रबंधन द्वारा श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए प्रदेश सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रेक्टर के माध्यम से सीमेंट प्लांट और अन्य औद्योगिक इकाइयों में कोर सेवाओं की अनुमति प्रदान की जाएगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के लगभग दो साल प्रभावित हुए हैं इस दौरान प्रदेश सरकार ने श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बाहर निकलने में प्रदेश सरकार का सहयोग करने में बीएमएस ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि बीएमएस की सभी जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा और उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। हाल ही में आयोजित हुई जेसीसी की बैठक में कर्मचारी एवं श्रमिक वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अगले बजट सत्र से पूर्व बीएमएस की बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की काफी समय से लम्बित समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीस मील श्रमिकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य श्रेणियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों से संबंधित उनके द्वारा की गई घोषणाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर टी-मेट के पदनाम को समाप्त कर इसे बदलकर टी-मेट कर दिया जाएगा।

इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के अध्यक्ष मदन राणा ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों और कामगारों की विकासात्मक मांगों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मजदूरों और श्रमिक वर्ग की विकासात्मक मांगों पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से आशा कार्यकर्ताओं, टेलरिंग शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक स्थायी नीति बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने का भी आग्रह किया।

श्रम आयुक्त रोहित जमवाल ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया और धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार आर.डी. धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव जे. सी. शर्मा, सचिव डॉ. अजय शर्मा, संदीप भटनागर, राजीव शर्मा और अमिताभ अवस्थी, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, सुरेंद्र ठाकुर, महासचिव बीएमएस यशपाल हेटा, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों सहित अन्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

एम्स बिलासपुर में ओपीडी सुविधा का शुभारंभ

शिमला/शैल। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आगामी छः महीनों के भीतर एम्स बिलासपुर को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा और क्षेत्र के लोगों के साथ प्रदेश के लोगों को राज्य में ही अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वे बिलासपुर में राज्य की लक्षित पात्र आबादी के शत-प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के ऐतिहासिक अवसर

पर कोविड टीकाकरण के अन्तर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि दिल्ली से बाहर एम्स की स्थापना करना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक परिकल्पना थी, क्योंकि वर्ष 1960 में दिल्ली में पहला एम्स स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 22 एम्स स्थापित किए जा रहे हैं और यह सब प्रधानमंत्री के प्रयासों से सम्भव हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा लगभग तीन वर्ष पहले रखी गयी थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िला को पीजीआई चंडीगढ़ का 500 करोड़ रुपये का सैटेलाइट सेन्टर मिला है।

इससे पहले सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जिला बिलासपुर के एम्स कोठीपुरा में ओपीडी जनता को समर्पित की। एम्स बिलासपुर के डॉ. कपिल शर्मा ने इस प्रतिष्ठित संस्थान की पहली ओपीडी मरीज जिला कुल्लू की रेखा का ईलाज भी किया। उन्होंने कोविड टीकाकरण में कार्यरत चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को इस अवसर पर सम्मानित किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि एम्स वास्तव में राज्य को केंद्र सरकार का एक अमूल्य उपहार है। उन्होंने कहा कि विश्व ने देश की बौद्धिक ताकत को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि नासा में कार्यरत 10 वैज्ञानिकों में से लगभग तीन वैज्ञानिक भारतीय हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत देश की शक्ति को पहचाना और कोरोना वायरस के विरूद्ध स्वदेशी टीका विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि विश्व के 100 देशों को भारत में निर्मित एजिनोमाइसिन और रेमडेसीवीर जैसी दवाओं की आपूर्ति की गयी। उन्होंने कहा कि देश में 123 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज तैयार की गई है और अन्य देशों को भी इसका निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, उद्यमियों पर किए गए विश्वास के कारण ही यह सम्भव हो पाया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने में एम्स बिलासपुर की ओपीडी सुविधा मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के लोगों को यहां हर प्रकार की बीमारी का सुपर स्पेशियलिटी उपचार की सुविधा मिलेगी और बिलासपुर में स्थित एम्स से प्रदेश के लाखों लोगों को ही नहीं अपितु पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी लाभ मिलेगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे पहाड़ी राज्य को महत्त्व प्रदान कर एम्स का उपहार देने के लिए प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आभारी है। जय राम ठाकुर ने कहा कि कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश पूरी तरह तैयार है। राज्य के अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता को 3,804 से बढ़ाकर 8,765 कर दिया गया है जिसकी क्षमता को बढ़ाकर 11,000 किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सभी महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं और सभी जिलों में कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है। प्रदेश के सभी जिलों के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और संस्थानों में आरटीपीसीआर सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आगामी छह वर्षों में एम्स बिलासपुर बनकर तैयार हो जाएगा और इस संस्थान में राज्य के लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ राजीव सैजल ने इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य एंव राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केन्द्रीय स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्यिों का स्वागत किया।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

एम्स के कार्य में प्रगति के संबंध में निदेशक एम्स एवं अन्य अधिकारियों द्वारा एक प्रेजेंटेशन भी दी गयी।

सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. राम लाल मारकंडा, ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी, विधायक, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, सचिव स्वास्थ्य अमिताभ अवस्थी, एम्स के अध्यक्ष प्रमोद गर्ग, एम्स बिलासपुर के निदेशक डॉ. वीर सिंह नेगी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

शक्तिपीठों से आरती दर्शन के सीधे प्रसारण के लिये एमएच वन चैनल के साथ समझौता पत्र पर हुये हस्ताक्षर

शिमला/शैल। जिला कांगड़ा के अधिग्रहित मन्दिरों के महत्व के प्रसार एवं घर बैठे श्रद्धालुओं को दर्शन उपलब्ध करवाने हेतु जिला प्रशासन प्रयासरत है। इसी कड़ी में जिला के तीन महत्वपूर्ण शक्तिपीठों, श्री चामुण्डा, श्री बज्रेश्वरी देवी कांगड़ा एवं श्री ज्वालामुखी मन्दिर की सुबह एवं शाम की आरतियों के सीधे प्रसारण हेतु निर्धारित निविदा प्रक्रिया अपनाने के उपरान्त एमएच-1 चैनल का चयन किया गया है।

जिला प्रशासन एवं एम.एच.-1 के मध्य इस सम्बंध में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता पत्र हस्ताक्षर के उपरान्त एमएच-1 चैनल पर इन तीन मन्दिरों की आरतियों का सीधा प्रसारण शुरु हो जायेगा। आयुक्त (मन्दिर)-एवं-जिलाधीश कांगड़ा ने इस अवसर पर कहा की जिला प्रशासन के इस प्रयास से श्रद्धालुओं को तो निश्चित रुप से लाभ मिलेगा अपितु राज्य में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा व मन्दिरों की आय में भी वृद्धि होगी। कोरोना काल में जो लोग मन्दिरों में नहीं आ पा रहे हैं, उन्हे भी दर्शन की सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु इस तरह की गतिविधियों को भविष्य में भी बढ़ावा देता रहेगा।

उपायुक्त डा. निपुण जिन्दल ने इन शक्तिपीठों से आरती दर्शन के सीधे प्रसारण के बारे जानकारी देते हुए कहा कि श्री ज्वालामुखी मन्दिर की आरती प्रतिदिन शीतकाल में सांय 8.30 से 9 बजे जबकि ग्रीष्मकाल में 9.30 बजे से 10 बजे, ब्रजेश्वरी मन्दिर की आरती शीतकाल में प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक, ग्रीष्मकाल में प्रातः 5 बजे से 6 बजे तथा शीतकाल और ग्रीष्मकाल में रात्रि 7 से 8 बजे प्रसारित की जाएगी।

इसी प्रकार श्री चामुण्डा मन्दिर से आरती दर्शन का सीधा प्रसारण शीतकाल और ग्रीष्मकाल में प्रतिदिन प्रातः 8 से 8.30 बजे और शीतकाल में सांय 6.30 बजे से 7 बजे और ग्रीष्मकाल में सांय 8 बजे से 8.30 बजे तक होगा। इन आरतियों का प्रसारण एम. एच.1 चैनल द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे ऐसे सभी श्रद्धालुओं के लिए लाइव आरती कारगर साबित होगी, जो श्रद्धालु माता मंदिर तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। इसके साथ ही लाइव आरती के माध्यम से इन शक्तिपीठों के बारे में देश ही नहीं अपितु विदेशों में रहने वाले लोगों तक भी जानकारी पहुंचेगी।

इस अवसर पर एमएच-1 चैनल की तरफ से सविता झिंगम, एडीएम रोहित राठौर, एस.डी.एम. धर्मशाला शिल्पी, एस.डी.एम. ज्वालामुखी मनोज कुमार, सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) राजिन्द्र कुमार व अधीक्षक मन्दिर शाखा कुलदीप अवस्थी उपस्थित रहे।

यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है ? यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

घातक होगा बैंकिंग संशोधन

इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस सबसे पहले ही दिन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का विधेयक पारित हो गया है। जब यह विधेयक लाया गया था तब भी इस पर संसद में कोई बहस नहीं हो पायी थी और अब वापसी के समय भी ऐसा ही हुआ है। इसी सत्र में क्रिप्टोकरंसी और बैंकिंग अधिनियम में संशोधन को लेकर भी विधेयक लाये जा रहे हैं। इन पर सदन में चर्चा हो पानी है या नहीं। इन्हें सिलेक्ट कमेटीयों को विस्तृत चर्चा के लिए भेजा जाना है या नहीं या सीधे पारित करवा लिया जाता है यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन यह ऐसे विधेयक हैं जिनका हर आदमी पर असर पड़ेगा। इसलिए इस संदर्भ में कुछ सवाल सार्वजनिक चर्चा के लिए उठाना आवश्यक हो जाता है। इन पर सवाल उठाने से पहले यह याद रखना होगा कि 2016 की नोट बंदी के बाद आज देश के बैंकों का एनपीए बढ़कर 10 खरब करोड़ हो चुका है और इसकी रिकवरी के लिए सरकार को बैड बैंक बनाना पड़ा है। यह ध्यान में रखना होगा की जब देश के बैंकों का एनपीए 10 खरब करोड़ हो चुका है तो वहां बैंकों की व्यवहारिक स्थिति क्या रह गयी होगी। यहां यह भी ध्यान में रखना होगा की नोटबदी से लेकर कोरोना की तालाबंदी तक सरकार के जो भी आर्थिक पैकेज आये हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रोत्साहन कर्ज लेने को लेकर दिया गया है। इसी दौरान 59 मिनट में एक करोड़ का कर्ज लेने की प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना भी आयी और शायद इसी सबका परिणाम है यह 10 ट्रिलियन करोड़ का एनपीए।

इस पृष्ठभूमि में आ रहे इन विधेयकों को लाने की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई और इससे किसको क्या लाभ मिलेगा यह विचारणीय सवाल हैं। बैंकिंग अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन पर बैंक कर्मचारी संगठनों ने तो ''बैंक बचाओ देश बचाओ'' के बैनर तले 1 दिन का प्रदर्शन करके यह कहा है कि इस संशोधन से सरकारी बैंकों को प्राइवेट सैक्टर को देने की योजना है। इससे बैंकिंग सेवाएं महंगी हो जाएंगी। यह भी जानकारी दी है कि अब तक 500 बैंक दिवालिया हो चुके हैं। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब भी यही सबसे बड़ा कारण था कि उस समय भी कई बैंक डूब चुके थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण ही आज तक देश के बैंक सुरक्षित चल रहे थे और जनता का विश्वास इन पर बना हुआ था। अब जब यह बैंक प्राइवेट सैक्टर के पास चले जाएंगे तो आम आदमी इन में अपना पैसा रखते हुए डरेगा। वैसे ही जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी तब जून 2014 में बैंकों का एनपीए करीब अढ़ाई लाख करोड़ था जो आज बढ़कर सितंबर 2021 में 10 खरब करोड़ हो चुका है। इससे सरकार की नीतियों का पता चलता है।

इसी परिदृश्य में क्रिप्टोकरंसी को लेकर विधेयक लाया जा रहा है एक समय आर बी आई ने क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रतिबंध को यह कहकर रद्द कर दिया था कि जब इसको लेकर आपके पास कोई कानून ही नहीं है तो प्रतिबंध का अर्थ क्या है। अब वित्त मंत्री ने यह कहा है कि क्रिप्टो पर प्रतिबंध नहीं लगाकर इसको रैगुलेट किया जाएगा। और इस नियमन की जिम्मेदारी सैबी की होगी। इसी के साथ ही यह भी कहा है कि क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं होगा। यहीं से आशंकाएं उठनी शुरू हो जाती है क्योंकि करंसी विनिमय का माध्यम होता है। करंसी से वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं।करंसी पर सरकार का नियंत्रण और अधिकार रहता है। करंसी से आप बैंक में खाता खोल सकते हैं। बैंक इस खाते का लेजर रखता है परंतु क्रिप्टो का बैंक से कोई संबंध ही नहीं है। इसका सारा ऑपरेशन डिजिटल है जो उच्च क्षमता के कंप्यूटर से संचालित होगा । एक कोड से ऑपरेट होगा। इस समय करीब एक दर्जन क्रिप्टोकरंसी प्रचलन में हैं। लेकिन सरकार के पास कोई नियन्त्रण नहीं है। ऐसे में क्रिप्टो पर कोई भी रैगुलेशन लाने से पहले इसके बारे में जनता को जागरूक किया जाना चाहिये। क्योंकि यह एक डिजिटल कैश प्रणाली है। जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। यह सिर्फ डिजीट के रूप में ही ऑनलाइन रहती है। इस पर किसी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। एक तरह से यह गुप्त रूप से पैसा रखने की विधा है। इसलिए इस संबंध में कोई भी रैगुलेशन लाने का औचित्य तब तक नहीं बनता जब तक इसे सामान्य लेन देन की प्रणाली के रूप में मान्यता नहीं दे दी जाती। इसके बिना यह काले धन और उसके विदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने का ही माध्यम सिद्ध होगा। इसलिए आज जिन आर्थिक परिस्थितियों में देश चल रहा है उनमें बैंकों को प्राइवेट सैक्टर को सौंपने की योजना और क्रिप्टो को रैगुलेट करने के अधिनियम लाना कतई देश के हित में नहीं होगा। इससे आम आदमी भी बैंक बचाओ देश बचाओ में कूदने पर विवश हो जायेगा।

भविष्य की कई संभावनाओं को टटोलने भारत आये हैं पुतिन

गौतम चौधरी

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर हैं। जिस प्रकार पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्ष के भारत आगमन पर समाचार माध्यमों का शोर होता है, पुतिन की यात्रा पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है लेकिन पुतिन का वर्तमान भारत दौरा न केवल भारत–रूस के लिए अहम है, अपितु तेजी से बदल रही दुनिया के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा है।

सबसे पहली बात, इस दौरे की अहमितय का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऐन कोराना काल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली मित्र देशों की सेना अभी हाल ही में अफगानिस्तान को छोड़ गयी और वहां फिर से तालिबानियों ने कब्जा जमा लिया है। इस बदलाव का असर भारत, पाकिस्तान, ईरान, चीन, मध्य एशियायी देशों के साथ ही रूस पर भी पड़ रहा है। यही नहीं अभी हाल ही में अफगान समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने–अपने ढ़ंग की बैठकें की। इस्लामाबाद और नई दिल्ली, दोनों बैठकों में रूसी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चौथी बात, भारत, चीनी विस्तारवाद को लेकर बेहद सशंकित है और उस आशंका से परेशान चीन को घेरने के लिए अमेरिकी नेतृत्व में बने क्वार्ड संगठन में शामिल हो गया है। भारत की सीमा पर चीन का दबाव बढ़ता जा रहा है। इधर भारत के पश्चिम और पूरब दोनों सीमाओं पर चीन समर्थक देश पाकिस्तान व म्यामार भी भारतीय सीमा पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इन चुनौतियों को लेकर भारत ज्यादा संवेदनशील है।

रूस, भारत का पुराना मित्र देश रहा है और कई मौकों पर भारत की सहायता करता रहा है। विकट से विकट परिस्थिति में रूस, भारत के साथ खड़ा रहा है। कई ऐसे भी मौके आए जब भारत को लेकर रूस ने सुरक्षा परिषद में अपनी सर्वोच्च शद्रि वीटो का प्रयोग किया। फिर कछ ही दिन पहले दुनिया के देश जलवायु परिवर्तन को लेकर बैठे थे। उस बैठक में भी अहम फेसले हुए, जिसका दूरगामी प्रभाव दुनिया पर पड़ने वला है। बैठक के फैसले दुनिया के कई देशों के विकास पर प्रतिकूल असर भी डाल सकता है। इसलिए भी पुतिन का भारत दौरा अहम बताया जा रहा है।

हालांकि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने अपनी विदेश नीति में रूस की अपेक्षा अमेरिका को ज्यादा महत्व दिया है लेकिन रूस लगातार भारत के साथ दोस्ती निभाते आ रहा है। जब कभी भारत को रूस की जरूरत पड़ी उसने सहयोग किया। भारत की मीडिया इस दौरे को लेकर गंभीर हो या नहीं लेकिन रूसी राष्ट्रपति का वर्तमान भारत दौरा बेहद महत्व का होने वाला है।

पुतिन के भारत दौरे की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यह इस साल रूसी राष्ट्रपति का दूसरा विदेश दौरा है। आजकल कोरोना वायरस के खतरे के कारण पुतिन विदेश यात्रा से परहेज कर रहे हैं। अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान पुतिन और पीएम मोदी मुलाकात करेंगे और कई अहम रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकता है। इससे पहले पुतिन ने साल 2018 में भारत की यात्रा की थी। पुतिन का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है कि जब भारत को इस साल के आखिर तक एस–400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है। भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बाद भी साफ कर दिया है कि वह रूस से एस–400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेगा।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कई बार पुतिन को बुला चुके हैं लेकिन रूसी राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे को टालते रहे हैं। पुतिन की इस यात्रा के ऐलान से यह साबित हो गया है कि रूस के लिए भारत के साथ रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। इस दौरे पर रूस और भारत के बीच एक समझौता हो सकता है जिसके तहत भारतीय नौसेना को आर्कटिक इलाके में उपस्थिति दर्ज कराने का मौका मिल जाएगा। माना जाता है कि हिंद प्रशांत के बाद आर्कटिक ही दुनिया का अगला संसाधन–जंग का मैदान बनने जा रहा है।

भारत और रूस अब तक 20 वार्षिक शिखर बैठक कर चुके हैं। इससे पहले साल 2019 में पीएम मोदी रूस के व्लादिवोस्तक शहर गए थे। उस दौरे में भारत ने रूस के इलाके में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया था। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा भागीदार देश है। भारत रूस से अत्याधुनिक एके–203 राइफल, युद्धपोत, फाइटर जेट और अन्य घातक हथियार ले रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरे पर भी कई अहम रक्षा समझौते हो सकते हैं।

एक बात यहां बता देना जरूरी होगा कि पुतिन ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में अमेरिका के खिलाफ एक नए प्रकार के ध्रुवीकरण की रणनीति अपना रखी है। उस रणनीति में बड़ी चतुराई से पुतिन आगे बढ़ते रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर न केवल अमेरिका को अपितु पूरे पश्चिमी जमात को बैकफुट पर ला कर खड़ा कर दिया। जिसमें सीरिया युद्ध, अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाये गये प्रतिबंध, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अमेरिकी हस्तक्षेप आदि शामिल है। यही नहीं पुतिन के प्रयास से ही ब्रिक्स का गठन किया गया और चीन के शंघाई सहयोग संगठन को बल मिला। हालांकि ब्रिक्स सदस्य देश, भारत व ब्राजिल में नेतृत्व परिवर्तन के बाद, इस संगठन की गति में थोड़ा अवरोध तो पैदा हुआ है लेकिन रूस एवं चीन ने इसे मजबूत करने की पूरी कोशिश की है। इन दिनों अमेरिका, ब्रिक्स के तीसरे सदस्य देश दक्षिण अफीका को भी कमजोर करने की कोशिश में लगा है लेकिन चीन व रूस अमेरिका की इस चाल को भी नाकाम करने में लगे हैं।

पुतिन के इस दौरे को शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स के साथ भी जोड़ कर देखा जा रहा है। पुतिन इन दोनों संगठनों के प्रति आशान्वित हैं। भारत इन दोनों संगठनों का अहम किरदार साबित हो रहा है। इसलिए भी पुतिन का भारत दौरा अहम माना जा रहा है। कोरोना के कारण दुनिया नए सोशल ऑडर की ओर बढ़ रही है। वैश्विक समाज व देश कौन–सा रूप ग्रहण करेगा, यह तय नहीं है लेकिन दुनिया को अपने तरीके से चलाने वाले देश भविष्य में भी अपनी अहमियत बनाए रखना चाहते हैं। कृतिम बुद्धिमत्ता और जेनेटिक अभियंत्रण भविष्य का हथियार भी है। भारतीय मेधा इसका बड़ा किरदार है। पुतिन संभावत: इस प्रकार की भविष्य की संभावनाओं को भी तलाशने के लिए भारत के दौरे पर आये हैं।

भारत पर्यावरण–अनुकूल क्षेत्र में बिजली चालित वाहन उद्योग का नेतृत्व करने के लिए तैयार

शिमला। भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कार बाजार है और निकट भविष्य में शीर्ष तीन में से एक होने की क्षमता रखता है – वर्ष 2030 तक लगभग 40 करोड़ लोगों को आवागमन संबंधी समाधान की आवश्यकता होगी। यह सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि देश को परिवहन – क्रांति की जरूरत है। महंगे, आयातित ईंधन द्वारा चालित तथा अवसंरचना विस्तार की समस्याओं को झेल रहे पहले से ही भीड़भाड़ वाले व उच्च वायु प्रदूषण से प्रभावित शहरों द्वारा और अधिक कारों को शामिल करना लगभग असंभव है। भारत के शहरों की 'साँसें थमने' लगेगी। इस परिवहन क्रांति में कई घटक होंगे – 'पैदल चलने की बेहतर सुविधा', बेहतर सार्वजनिक परिवहन, रेलवे, सड़कें – और बेहतर कारें। इनमें से कई 'बेहतर कारें' बिजली – चालित होंगी। परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की एक भरोसेमंद वैश्विक रणनीति रही है – बिजली – चालित वाहनों द्वारा आवागमन। भारत उन गिने – चुने देशों में से एक है, जो वैश्विक ईवी 30/30 अभियान का समर्थन करते हैं, जिसके तहत 2030 तक नए वाहनों की बिक्री में कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सा बिजली – चालित वाहनों के होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में हाल ही में संपन्न जलवायु परिवर्तन पर कॉप26 में पांच तत्वों, 'पंचामृत' की बात कही है, जो इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न विचारों की रूपरेखा को सामने रखा, जैसे भारत की ऊर्जा जरूरतों का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा किया जायेगा, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम किया जाएगा और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल किया जायेगा। ये लक्ष्य हमारी भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के लिए तय किए गए हैं, ताकि वे एक सुरक्षित और समृद्ध जीवन का आनंद ले सकें।

पेरिस समझौते के तहत स्थापित वैश्विक जलवायु कार्यसूची में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात कही गयी है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को सीमित किया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए बिजली – चालित वाहनों (ईवी) को प्राथमिकता दी जा रही है। अनुमान है कि यह रणनीति, समग्र ऊर्जा सुरक्षा स्थिति में सुधार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि देश कच्चे तेल की कुल आवश्यकताओं का 80 प्रतिशत से अधिक आयात करता है, जिसकी लागत लगभग 100 बिलियन डॉलर है। उम्मीद है कि ईवी उद्योग, रोजगार सृजन के लिए स्थानीय ईवी विनिर्माण उद्योग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। दूसरी ओर, ग्रिड को समर्थन करने वाली विभिन्न सेवाओं के माध्यम से, उम्मीद है कि ईवी उद्योग ग्रिड को मजबूती प्रदान करेगा तथा सुरक्षित और स्थिर ग्रिड संचालन को जारी रखते हुए उच्च नवीकरणीय ऊर्जा पहुँच को आसान बनाने में मदद करेगा।

आज वैश्विक विद्युत – परिचालित आवागमन क्रांति की परिभाषा बिजली – चालित वाहन (ईवी) के तेज विकास से दी जाती है। एक अनुमान के मुताबिक, आज बिकने वाली प्रत्येक सौ कारों में से दो बिजली – चालित होती हैं। इसे बिजली – चालित वाहनों (ईवी) की बिक्री में दर्ज की जा रही तेज वृद्धि से समझा जा सकता है, वर्ष 2020 के लिए ईवी की बिक्री 2.1 मिलियन तक पहुंच गई है। 2020 में ईवी की कुल संख्या 8.0 मिलियन थी, वैश्विक वाहन स्टॉक में ईवी का हिस्सा 1 प्रतिशत था, जबकि वैश्विक कार बिक्री में ईवी का हिस्सा 2.6 प्रतिशत दर्ज किया गया। वैश्विक स्तर पर बैटरी की गिरती लागत और बढ़ती प्रदर्शन क्षमता से पूरी दुनिया में ईवी की मांग को गति मिल रही है।

यह अनुमान है कि 2020 – 30 तक भारत की बैटरी की कुल मांग 900 – 1100 गीगावाट प्रति घंटा की हो जायेगी। लेकिन भारत में बैटरी की उत्पादक इकाइयों की अनुपस्थिति और इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एकमात्र आयात पर निर्भरता के कारण चिंता बढ़ गयी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2021 में एक बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के लिथियम – आयन सेलों का आयात किया था। यह एक अलग बात है कि बिजली के क्षेत्र में यहां इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी भंडारण की पैठ बहुत कम है। भारत के लिए जहां अभी इस अवसर को भुनाना बाकी है, वहीं वैश्विक उत्पादक बैटरी के उत्पादन पर अधिक दांव लगा रहे हैं और तेजी से गीगा – फैक्ट्रीज से हटकर टेरा – फैक्ट्रीज की ओर बढ़ रहे हैं।

हाल के प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों के बीच, ई – आवागमन और नवीकरणीय ऊर्जा (2030 तक 450 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य) को बढ़ावा देने से संबंधित सरकार की विभिन्न पहलों को देखते हुए बैटरी भंडारण के सामने देश में सतत विकास को बढ़ावा देने का एक बड़ा अवसर है। प्रति व्यक्ति आय के बढ़ते स्तरों के साथ – साथ मोबाइल फोन, यूपीएस, लैपटॉप, पावर बैंक आदि के क्षेत्र में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्रियों की जबरदस्त मांग हो रही है, जिनके लिए

डॉ. महेंद्र नाथ पांडे
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री

उन्नत किस्म की रासायनिक बैटरी की जरूरत होती है। यह परिस्थिति उन्नत किस्म की बैटरियों के उत्पादन को वैश्विक स्तर पर 21वीं सदी के सबसे बड़े आर्थिक अवसरों में से एक बनाती है।

भारत सरकार ने देश में बिजली – चालित वाहनों (ईवी) के इकोसिस्टम को विकसित करने और इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं। इन उपायों में उपभोक्ता पक्ष के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन से संबंधित पुन: प्रतिरूपित त्वरित संयोजन (फेम II) योजना (10,000 करोड़ रुपये) से लेकर आपूर्तिकर्ता पक्ष के लिए उन्नत रासायनिक सेल से संबंधित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (18,100 करोड़ रुपये) और अंत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं के लिए ऑटो एवं ऑटोमोटिव से जुड़े घटकों के लिए हाल ही में शुरू की गयी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (25,938 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

इस प्रकार, अर्थव्यवस्था में एकीकरण के इन सभी अग्रगामी और पश्चगामी तंत्रों द्वारा आने वाले वर्षों में अधिक विकास हासिल किये जाने की उम्मीद है। यह भारत को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ बनाने, इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहनों को अपनाने की दिशा में एक लंबी छलांग लगाने में सक्षम बनाएगा। इससे न सिर्फ देश को विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी, बल्कि यह भारत को बिजली – चालित वाहनों के निर्माण और कॉप24 पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के बेहतर अनुपालन के मामले में एक वैश्विक अगुआ भी बनाएगा।

इन तीनों योजनाओं में कुल मिलाकर लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है, जोकि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी और देश में पूर्ण घरेलू आपूर्ति श्रृंखला के विकास एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ – साथ बिजली चालित वाहनों तथा बैटरी की मांग पैदा करने में सहायक साबित होगी। इस कार्यक्रम से तेल के आयात बिल में लगभग दो लाख करोड़ रुपये की कमी और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के आयात बिल प्रतिस्थापन की परिकल्पना की गयी है।

मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण सार्वजनिक एजेंसियों और निजी उद्यमियों, दोनों को सहयोग की एक यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा जिससे देश को अकल्पनीय पैमाने पर लाभ होगा।

4669 हेक्टेयर बंजर छोड़ी भूमि पर मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना से फिर से आयी बहार

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 175 करोड़ रुपए व्यय, राज्य के 5535 किसान हो रहे लाभान्वित

शिमला। प्रदेश की कृषि जलवायु नकदी फसलों के उत्पादन के लिए अति उत्तम है। इसके अलावा यहां पारंपरिक खेती से भी लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। कई क्षेत्रों में किसानों की कड़ी मेहनत से उगायी गई फसलों को बेसहारा व जंगली जानवरों से काफी नुकसान पहुंचता है। इससे बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना आरंभ की है।

इस योजना के अंतर्गत कृषकों को सौर ऊर्जा चालित बाड़ लगाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। व्यक्तिगत स्तर पर सौर ऊर्जा बाड़ लगाने के लिए 80 प्रतिशत तथा समूह आधारित बाड़बंदी के लिए 85 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान इसमें किया गया है। बाड़ को सौर ऊर्जा से संचारित किया जा रहा है। बाड़ में विद्युत प्रवाह से बेसहारा पशुओं, जंगली जानवरों एवं बंदरों को दूर रखने में मदद मिल रही है।

प्रदेश सरकार ने किसानों की मांग तथा सुझावों को देखते हुए कांटेदार तार अथवा चेनलिंक बाड़ लगाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान और कम्पोजिट बाड़ लगाने के लिए 70 प्रतिशत उपदान का भी प्रावधान किया है।

अच्छी बात यह है कि प्रदेश में किसानों का इस योजना के प्रति उत्साह एवं विश्वास लगातार बढ़ा है और लाभार्थियों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ी है। किसानों का कहना है कि जंगली जानवरों विशेष तौर पर बंदरों के उत्पात से फसलें खराब होने के कारण उनका खेती के प्रति उत्साह कम हो गया था, मगर मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना वरदान बनकर आयी है। इससे बंदरों के उत्पात से उनकी फसलों का बचाव संभव हुआ है। इसमें सोलर फैंसिंग के साथ – साथ कांटेदार बाड़बंदी का प्रावधान जुड़ने से अन्य जंगली व बेसहारा जानवरों से भी फसल सुरक्षित हुई है।

योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 175.38 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। इस योजना के लागू होने के उपरांत प्रदेश में लगभग 4,669.20 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि की रक्षा की गयी है जो बेसहारा पशुओं, जंगली जानवरों और बंदरों के खतरे के कारण बंजर पड़ी थी। प्रदेश के लगभग 5,535 किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।

मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का लाभ उठाने के लिए किसान व्यक्तिगत तौर पर अथवा किसान समूह के रूप में नजदीक के कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी अथवा विषयवाद विशेषज्ञ (एसएमएस) के माध्यम से कृषि उपनिदेशक के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। विभाग के वृत्त, विकास खंड एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में आवेदन फॉर्म उपलब्ध रहते हैं। आवेदन के साथ उन्हें अपनी भूमि से संबंधित राजस्व दस्तावेज संलग्न करने होंगे। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि विभाग के एक अनुमान के अनुसार प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 70 प्रतिशत लोग सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व इससे जुड़े क्षेत्रों का योगदान लगभग 13. 62 प्रतिशत है। प्रदेश में लगभग 9. 97 लाख किसान परिवार हैं तथा 9. 44 लाख हैक्टेयर भूमि पर काश्त होती है। यहां औसतन जोत का आकार लगभग 0.95 हैक्टेयर है। प्रदेश में 88.86 प्रतिशत किसान सीमान्त तथा लघु वर्ग के हैं जिनके पास बोई जाने वाली भूमि का लगभग 55.93 प्रतिशत भाग है। 10.84 प्रतिशत किसान मध्यम श्रेणी के हैं और 0.30 प्रतिशत किसान ही बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं।

ऐसे में प्रदेश सरकार की खेत संरक्षण योजना सीमान्त, लघु व मध्यम वर्ग के किसानों के लिए वरदान बन कर आयी है। बेसहारा व जंगली जानवरों के उत्पात से खेती – किसानी से किनारा कर रहे कृषक फिर से खेतों की ओर मुड़े हैं और यह योजना हिमाचल में सुरक्षित खेती की नई इबारत लिख रही है।

वर्ष 2022 और 2023 में संभावित रिक्तियों के दृष्टिगत लिपिक के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के स्थान पर लिपिक के 100 पद भरने तथा वर्ष 2022 और 2023 में संभावित रिक्तियों के दृष्टिगत लिपिक के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में स्वर्ण जयन्ती परम्परागत बीज सुरक्षा एवं संवर्द्धन योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पारम्परिक फसलों के उत्पादन व उत्पादक क्षमता में वृद्धि, पारंपरिक फसलों की पोषण सुरक्षा में सुधार और किसानों की आय दोगुनी करना है।

मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2020-21 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के अन्तर्गत कक्षा पहली, तीसरी, छठी और नवीं कक्षा के बच्चों को स्कूल बैग प्रदान करने के उद्देश्य से इनकी खरीद, आपूर्ति और वितरण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ई-निविदा के एल-1 निविदादाता मैसर्ज हाई स्पिरिट कमर्शियल वैंचर्ज प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृति प्रदान की। इससे प्रदेश की विभिन्न राजकीय पाठशालाओं में अध्ययनरत लगभग तीन लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा और इस पर लगभग नौ करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी।

बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए पथ कर (टॉल) इकाइयों की टॉल फीस को कम करने/इसमें छूट देने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय पिछले वर्ष जून, 2020 से सितम्बर, 2020 के मध्य राज्य में केवल आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में लगे वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति प्रदान करने के कारण इन इकाइयों को हुए घाटे विशेष तौर पर ऐसी टॉल इकाइयां, जिन्होंने अपने नवीनीकरण के लिए पूरी राशि का भुगतान किया था, उनकी ओर से पथ कर फीस में छूट अथवा इसे कम करने तथा मासिक किस्त के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई मांग के आधार पर लिया गया।

मंत्रिमण्डल में मैसर्ज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का अनुबंध 6.18 करोड़ रुपये के बिना किसी कर भुगतान के साथ 1 मई, 2021 से 30 अप्रैल, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया बशर्ते आबकारी विभाग ये सेवाएं आंतरिक स्तर पर अपने अधीन लाने के लिए तंत्र विकसित करेगा।

मंत्रिमंडल ने मंडी में नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए दि सरदार पटेल यूनिवर्सटी, मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना एवं विनिमयन) बिल, 2021 प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

बैठक में प्रदेश में सतत् परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बिजली चालित वाहनों के विकास और विद्युत चालित वाहनों के निर्माण में वैश्विक केन्द्र बनाने और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में इन वाहनों के लिए चार्जिंग अधोसंरचना विकसित करने तथा विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण में लगे उद्योगों को अनुदान और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के दृष्टिगत इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला की फतेहपुर तहसील के अन्तर्गत रे में उप- तहसील खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणी के 12 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में शिमला जिला की जुन्गा उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

कुल्लू जिला की भुंतर तहसील के अन्तर्गत जरी में उप-तहसील खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

बैठक में शहरी क्षेत्रों में लागू

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अन्तर्गत स्ट्रीट वेंडर्ज व रेहड़ी वालों इत्यादि के लिए स्वीकृत ऋण के लिए हाइपौथिकेशन अनुबंध पर स्टाम्प डयूटी घटाकर न्यूनतम 10 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र के सवाड़ में जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के करसोग क्षेत्र के अंतर्गत चुराग में जल शक्ति विभाग का उपमण्डल और माहुनाग स्थित सवामाहूं में जल शक्ति विभाग का सेक्शन कार्यालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में चम्बा जिला के पांगी क्षेत्र के किलाड़ में जल शक्ति विभाग का मण्डल तथा भरमौर क्षेत्र के साच (पांगी) में जल शक्ति विभाग का उप मण्डल खोलने को स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के भरमौर विधानसभा के अन्तर्गत शिक्षा खण्ड मैहला की ग्राम पंचायत सुनारा के ततारी गांव, शिक्षा खण्ड गैहरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत फटी गैहरा के अटाला गांव, शिक्षा खण्ड पांगी स्थित किलाड़ की ग्राम पंचायत शूण के गांव टांवा और ग्राम पंचायत सेचू के गांव पुष्वाश चास्क राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं खोलने को स्वीकृति दी।

बैठक में मण्डी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत रैंस गांव तथा सुन्दरनगर विधानसभा क्षेत्र के चिराल में प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के आनी खण्ड में स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला देवरी को स्तरोन्नत कर राजकीय माध्यमिक पाठशाला बनाने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

बैठक में सोलन जिला के राजकीय महाविद्यालय कंडाघाट में गणित विषय की कक्षाएं प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मेडस्वान फाउंडेशन को पूर्व में जारी लैटर ऑफ अवार्ड को कार्योत्तर स्वीकृति देने तथा चार वर्षों के लिए इस फाउंडेशन को लैटर ऑफ अवार्ड की स्वीकृति और प्रदेश में एनएए-108/जेएसएसके-102 एम्बुलेंस के संचालन और मरम्मत के लिए इसके साथ त्रिकोणीय समझौता करने को अपनी स्वी ति प्रदान की गई।

बैठक में जिला मंडी के सरोआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा बस्सी में स्वास्थ्य उपकेंद्र आवश्यक पदों के सृजन सहित खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू की लग घाटी के दुंगधरी गड़ में आवश्यक पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला मंडी के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक पदों के सृजन के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला की कुल्लू तहसील के मोहाल रोपड़ी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को भुटी में 33/11 केवी 2 गुणा 1. 16 एमवीए उप मण्डल स्थापित करने के लिए 0-12-00 हेक्टेयर भूमि 99 वर्षों की लीज पर 1200 रुपये प्रति वर्ष के लीज मूल्य पर देने का निर्णय लिया।

बैठक में वायु सेना केन्द्र डलहौजी के लिए भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को नियमों और निर्देशों में छूट प्रदान करते हुए एक विशेष मामले के तहत मोतीटिब्बा में 766 वर्गमीटर भूमि एक रुपये टोकन मूल्य पर स्थानान्तरित करने को स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के मनाली में बहुमंजिला कार पार्किंग और बस अड्डे के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्धन और विकास प्राधिकरण को मोहाल कस्वाती नसोगी, मनाली और मोहाल कस्वाती छियाल विहा, मनाली में 1-65-83 हेक्टेयर वन भूमि 99 वर्षों की लीज पर 16,583 रुपये प्रतिवर्ष के लीज मूल्य और इसमें प्रति पांच वर्ष पश्चात् पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी पर प्रदान करने को अपनी स्वीकृति दी।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला की धर्मशाला तहसील और मौजा के अन्तर्गत 00-05-10 हेक्टेयर भूमि कांगड़ा आर्ट्स प्रोमोशन सोसायटी (पंजीकृत), धर्मशाला को 99 वर्ष की लीज पर 13158 रुपये वार्षिक लीज मूल्य जिसमें कि प्रति पांच वर्ष पश्चात पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी पर प्रदान करने को भी स्वी ति दी।

बैठक में सिरमौर जिला में स्थानीय लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत पटवार वृत्त चाड़ना को नौहराधार तहसील से उप-तहसील हरिपुरधार में स्थानान्तरित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला में पुलिस चैकी मैहतपुर को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों के सृजन को अपनी स्वीकृति दी।

बैठक में कांगड़ा जिला के नूरपुर स्थित पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय को स्तरोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करने को स्वीकृति दी।

मंत्रिमण्डल में मण्डी जिला में ग्राम पंचायत धरोट को विकास खण्ड गौहर से स्थानान्तरित कर विकास खण्ड निहरी में शामिल करने को अपनी स्वीकृति दी।

बैठक में कुल्लू जिला के दयोठा और कोट में आवश्यक पदों के सृजन के साथ स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के खन्यौल बगड़ा, चरखड़ी, सेरी और जयदेवी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इन केन्द्रों के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मंडी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दवाड़ा को 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

जिला मंडी विशेषकर जंजैहली क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने जंजैहली स्थित पर्यटन विभाग के सांस्कृतिक केंद्र के स्तरोन्नयन, संचालन तथा प्रबंधन का कार्य एकल बोली लगाने वाले मेसर्स गेबल्स प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड चंडीगढ़ को प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मंडी में पर्यटन विभाग के पी.पी.पी मोड के तहत सुविधा केंद्र के स्तरोन्नयन, संचालन तथा प्रबंधन को सबसे अधिक बोली लगाने वाले मेसर्ज एग्री कन्सलटन्टस प्राईवेट लिमिटेड नई दिल्ली-मेसर्ज लॉर्डस इन हॉटल्स एवं डवेल्पर्स प्राईवेट लिमिटेड (कन्सोरटियम) को प्रदान करने का निर्णय लिया।

बैठक में आयुर्वेदिक अस्पताल केलंग का नाम श्री टाशी छेरिंग आयुर्वेदिक अस्पताल केलंग रखने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय प्रसिद्ध चिकित्सक को सम्मान प्रदान करने के लिए लिया गया।

मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के श्री गुग्गामाड़ी मेला सुबाथू को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया।

बैठक में राज्य में कोविड-19 की स्थिति तथा तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर एक प्रस्तुति भी दी गई।

बैठक में राजस्व मामलों के सुचारू निस्तारण के लिए राज्य के उपमण्डलों में सी श्रेणी के कार्यालय कानूनगो के 41 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में जिला शिमला की तहसील कोटखाई में नई सृजित उप-तहसील कलबोग के सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न वर्गों के 12 पदों को भरने का निर्णय भी लिया।

मंत्रिमंडल में वन विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में अभियोजन विभाग में डेलीवेज आधार पर सेवादार के 30 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सफाई कर्मचारियों के 28 पद भरने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश ऊन संघ में ऊन निकालने वालों के दस पदों को भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अधिष्ठाता के पांच पद और निदेशक के दो पद भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन विभाग में मत्स्य अधिकारी के दो पदों और मत्स्य क्षेत्रीय सहायक के 20 पदों को सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल निरीक्षकों के सात पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने अटल बिहारी वाजपेयी अभियांत्रिकी संस्थान प्रगतिनगर जिला शिमला के पॉलिटेक्निक विंग में कंप्यूटर अभियांत्रिकी के वरिष्ठ लेक्चरर और इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी का एक-एक पद सृजित करने को अपनी सहमति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने अभियोजन विभाग में कनिष्ठ आशुलिपिक के दो पदों को सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया।

1376 करोड़ रुपये निवेश के 19 नए व विस्तार प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान

शिमला/शैल। राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 20वीं बैठक

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में नए औद्योगिक उद्यम स्थापित करने और वर्तमान इकाईयों के विस्तार के 19 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें लगभग 1,376.93 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिससे लगभग 2,266 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। इससे यह प्रदर्शित होता है कि आर्थिक मंदी के बावजूद राज्य निवेश को निरंतर आकर्षित कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस राष्ट्रपति कलर अवार्ड से सम्मानित

शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा ऐतिहासिक रिज मैदान में प्रेजिडेंट कलर अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर बतौर मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर विशेष

अतिथि के रूप में उपस्थित थे। राज्यपाल ने प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति कलर अवार्ड से सम्मानित किया। यह पुरस्कार पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने प्राप्त किया।

राज्यपाल ने प्रदेश पुलिस को प्रेजिडेंट कलर मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि यह भारत का आठवां राज्य पुलिस बल है जिसे यह गौरव प्राप्त हुआ है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस को प्रेजिडेंट कलर पुरस्कार मिलना एक विशेष उपलब्धि है जो यह साबित करता है कि हिमाचल पुलिस प्रदर्शन, निपुणता, अखण्डता, मानव अधिकारों की सुरक्षा और अन्य मानकों के साथ मानवता की सेवा में उच्च स्थान रखती है।

उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार प्रदेश पुलिस के कर्मियों के अथक योगदान के लिए प्रदान किया गया है जिन्होंने विश्वसनीय, व्यवसायिक और ईमानदारी से एक जन हितैशी के रूप में वर्षों अथक कार्य किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह अवार्ड पुलिस कर्मियों को और बेहतर ढंग से जन सेवा के लिए प्रोत्साहित करेगा।

इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश पुलिस को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रेजिडेंशियल अवार्ड प्राप्त होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह किसी भी पुलिस कर्मी के जीवन की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। हिमाचल प्रदेश पुलिस देश का आठवां पुलिस बल है जिसे प्रेजिडेंशियल अवार्ड प्राप्त हुआ है।

पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि प्रेजिडेंटस कलर केवल एक पुरस्कार नहीं अपितु यह एक जिम्मेदारी भी है जिसे हिमाचल प्रदेश पुलिस को अब और अधिक ईमानदारी, दक्षता और अनुशासन के साथ निभाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस का प्रत्येक जवान देव भूमि हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा और यहां शांति बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने राज्यपाल को प्रेजिडेंटस कलर पुरस्कार प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।

इससे पूर्व राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया।

हिमाचल के लिए 2095 करोड़ रुपये की एडीबी परियोजना को सैद्धान्तिक स्वीकृति:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लिए एशियन विकास बैंक की 2095 करोड़ रुपये की अधोसंरचना विकास परियोजना के लिए सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्राप्त करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि इसमें से 90 प्रतिशत ऋण राशि होगी, जो भारत सरकार द्वारा समर्थित होगी जबकि 10 प्रतिशत राज्य का हिस्सा होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक विशेष श्रेणी का राज्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में नये पर्यटन स्थलों को विकसित करने के अतिरिक्त मौजूदा पर्यटन स्थलों का रख-रखाव, सुधारीकरण और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत मौजूदा पर्यटन स्थलों से भीड़भाड़ व पर्यटकों के भारी दबाव को कम करने के लिए इको-टूरिज्म को बढ़ावा देकर राज्य के अनछुये गंतव्यों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष इस मामले को उठाया था तथा पर्यटन मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुति दी है। उन्होंने कहा कि एशियन विकास बैंक (एडीबी) से फंडिंग के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना को दो वित्तांश में क्रियान्वित किया जाएगा। पहले वित्त भाग में 900 करोड़ रुपये से अधिक जबकि दूसरा वित्त भाग 1100 करोड़ रुपये से अधिक का होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा और यह परियोजना अगले वर्ष मार्च से तेजी पकड़ेगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन से राज्य में पर्यटन गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, जिससे यहां विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा और विश्व के कोने-कोने से पर्यटकों को हिमाचल आने के लिए आकर्षित किया जा सकेगा।

आकांक्षी ज़िलों के समावेशित विकास में चम्बा को मिला देश में दूसरे स्थान

शिमला/शैल। देश के आकांक्षी ज़िलों के समग्र और समावेशी विकास में निरन्तर सुधार के नीति आयोग द्वारा आकलन में हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा ने दूसरा स्थान पाया है। इस उपलब्धि के लिए चम्बा के विभिन्न

विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई देते हुए चम्बा-कांगड़ा के लोकसभा सदस्य किशन कपूर ने कहा है केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयास से प्रदेश के इस पिछड़े ज़िले में विकासात्मक कार्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नीति आयोग के इस आकलन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सांसद किशन कपूर ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले आकांक्षी ज़िला चम्बा में विगत तीन वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं उनके प्रभावी कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकार और जिला के अधिकारियों का है और यह अपार हर्ष का विषय है कि नीति आयोग ने प्रदेश और जिला के कार्य को श्रेष्ठ आंका है।

सांसद किशन कपूर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जन- प्रतिनिधि की अध्यक्षता में दिशा जैसी विकास कार्यों के लिये गठित समितियों के प्रभावी मूल्यांकन से भी चम्बा ज़िला में विकास कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ रहे हैं।

सांसद किशन कपूर ने कहा कि देश से आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने वर्ष वर्ष 2018 में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े ज़िलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता के लिये आकांक्षी ज़िला के लिए विशेष कार्यक्रम बनाये।इसके अंतर्गत देश के 28 राज्यों से 115 ज़िलों की पहचान की गई थी जिनमें प्रदेश का चम्बा जिला भी सम्मिलित है। यह कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा संचालित और राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य वास्तविक समय में प्रगति के माध्यम से 5 मुख्य क्षेत्रों के 49 संकेतकों पर आकांक्षी ज़िलों का मूल्यांकन करना है। इसके तहत विभिन्न जिलों की प्रगति का मूल्यांकन देश एवं राज्य के सबसे प्रगतिशील जिले से अंतर के आधार पर किया जाता है। इसके पश्चात् आकांक्षी जिलों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है।

वोट से ही ताकतवर होता है लोकतन्त्र

धर्मशाला। जिला निर्वाचन विभाग कांगड़ा द्वारा चलाए जा रहे ''मतदाता जागरूकता कार्यक्रम'' के तहत सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग कांगड़ा के

कलाकारों ने राजकीय महाविद्यालय मटौर में कार्यक्रम आयोजित किया।

कलाकारों ने गीत-संगीत तथा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को बताया कि वोट से ही लोकतन्त्र ताकतवर होता है। उन्होंने बताया कि जिसकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूरी होती है। वह अपना वोट अवश्य बनाएं और यदि किसी के वोटर कार्ड में त्रुटि है तो उसे भी मतदाता अवश्य सही करवा ले ताकि आने वाले चुनावों में मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें।

कलाकारों ने बताया कि प्रशासन द्वारा प्रत्येक पंचायत के मतदान केंद्रों में नामित अधिकारी बिठाये गये हैं। कोई भी व्यक्ति 9 दिसंबर 2021 तक इन मतदान केंद्रों में जाकर वोटर कार्ड बनवा सकता है और त्रुटि को भी सही करवा सकता है।

कलाकारों ने बताया कि वोटर कार्ड बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल सरल है। मतदान केंद्र में जाकर कोई भी व्यक्ति अधिकारी द्वारा दिए गए फार्म को भर आधार कार्ड या मैट्रिक का सर्टिफिकेट व दो फोटो ले जाकर अपना वोटर कार्ड बनवा सकता है।

इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्य शुभ्रा गुप्ता, प्रो0 रजनी शर्मा, प्रो0 दिनेश जम्बाल, प्रो0 परवेश गिल सहित कॉलेज के छात्र एवं छात्राएं मौजूद थे।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार व मज़दूर ईश्रम पोर्टल करवाएं पंजीकरण:उपायुक्त

चंबा। उपायुक्त डीसी राणा ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार व मज़दूर ईश्रम पोर्टल https://eshram.gov.in

पर पंजीकरण अवश्य करवाएं ।

पंजीकरण के लिए 16-59 वर्ष के आयु वर्ग के सभी मनरेगा मज़दूर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, मिड डे मील वर्कर, दूध बेचने वाले, मछुआरे, कन्स्ट्रक्शन काम में लगे मज़दूर, फेरीवाले, रिक्शा चालक, खेतों में काम करने वाले मज़दूर, घरों में काम करने वाले लोग, महिलाऐं, छोटे दुकानदार और दुकानों पर काम करने वाले वर्कर पात्र होंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि पंजीकरण के लिए आयकर दाता पात्र नहीं होंगे। पंजीकृत व्यक्ति विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।

डीसी राणा ने बताया कि पंजीकरण करने पर एक कार्ड मिलेगा। यह एक स्थायी कार्ड होगा और जीवन भर के लिए मान्य है। पंजीकरण के बाद लाभार्थियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा भविष्य में असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। असंगठित कामगार ईश्रम पोर्टल पर जाकर या निकटतम सीएससी या लोक मित्र केन्द्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण निःशुल्क है। कामगारों को सीएससी या लोक मित्र केन्द्र ऑपरेटर सहित किसी संस्था को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

उपायुक्त ने लोगों से भी आहवान किया है कि यदि आपके घर, व्यापार, कार्यालय इत्यादि में ऐसे कामगार जुड़े हैं तो उनका पंजीकरण अवश्य करवाएं।

कोरोना के नए वैरिएंट 'ओमिक्रॉन' को लेकर पूरी तरह सतर्क है हिमाचल सरकार

मण्डी। हिमाचल में कोरोना के नए वैरिएंट 'ओमिक्रॉन' का कोई मामला नहीं है। लेकिन हिमाचल सरकार इसकी किसी भी संभावना से निपटने को लेकर पूरी तरह सतर्क है। इसके मद्देनजर जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल भंगरोटू का दौरा किया और अस्पताल प्रबंधन से 'ओमिक्रॉन' की किसी भी संभावना से निपटने को लेकर पूर्व तैयारियों का ब्योरा लिया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों के उपचार और देखभाल की व्यवस्था जानने के अलावा ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य प्रबंधों की जानकारी ली। मंत्री ने सभी से सतर्कता और बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया। लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉजेल एवं अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश मोहन ने जलशक्ति मंत्री को कोविड अस्पताल भंगरोटू में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का ब्योरा दिया। उन्होंने बताया कि मंडी समेत पूरे हिमाचल में 'ओमिक्रॉन' का कोई मामला नहीं आया है। वर्तमान में जिला में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल भंगरोटू में वर्तमान में केवल 4 मरीज उपचाराधीन हैं। अस्पताल प्रबंधन की कोविड से जुड़ी किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से निपटने को लेकर पूरी तैयारी है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

कोविड को लेकर "Covid vaccination voluntary hasn't mandated vaccination" केंद्र सरकार का सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र

- क्या इस शपथ पत्र के बाद भी कोई अधिकारी टीकाकरण के आदेश जारी कर पायेगा
- क्या आरोग्य सेतु एप पर भी सरकार का ऐसा ही स्टैंड नहीं रहा है

शिमला/शैल। कोविड वैक्सीन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के पूर्व सदस्य डॉक्टर जैकव पुलियेल ने एक याचिका दायर करके वैक्सीन के संबंध में हुए ट्रायल्स का डाटा उपलब्ध करवाने का आग्रह किया था। इस याचिका की पैरवी सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कर रहे हैं। यह याचिका शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राय और बीआर गवई की पीठ में चल रही है। इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह भी रखा गया है कि **vaccine mandates are not proportionate to personal liberty** इसमें कई राज्य सरकारों के निर्देशों का नाम लेकर जिक्र किया गया है। अदालत ने इन सभी राज्यों को इसमें पार्टी बनाने के निर्देश देते हुये इस आरोप का कड़ा संज्ञान लिया है। पिछले सप्ताह सुनवाई के लिए आये इस मामले में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय ड्रग्ज स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से दायर किये गये शपथ पत्र में कहा गया है कि कोविड – 19 के वैक्सीनेशन के लिए कोई वैधानिक अनिवार्यता नहीं रखी गयी है और यह वैक्सीनेशन एकदम ऐच्छिक है। यह शपथ पत्र सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया है। इसलिए इस पर संदेह नहीं किया जा सकता। इस शपथ पत्र से कोविड – 19 की गंभीरता को लेकर कई बुनियादी सवाल उठ खड़े होते हैं।

यदि पिछले कुछ वर्षों पर नजर डाली जाए तो यह सामने आता है कि हर 10 – 12 वर्ष के अंतराल में कोई न कोई बीमारी आती रही है। कोविड – 19 से पहले स्वाइन फ्लू था। और स्वाइन फ्लू तथा कोविड के लक्षणों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों एक जैसे ही गंभीर कहे गये हैं। देश में हर जन्म और मरण का पंजीकरण होता है यह नियम है। मरण के आंकड़े संसद में गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल द्वारा रखे जाते हैं। 2018 तक के आंकड़े संसद में रखे जा चुके हैं और इनके अनुसार देश में 2018 में 69 लाख लोगों की मौत हुई है। हिमाचल का आंकड़ा ही 48000 रहा है। इसी आंकड़े के में स्वाइन फ्लू से हुई मौतें भी शामिल हैं। लेकिन इन मौतों के बावजूद भी कोई लॉकडाउन घोषित नही किया गया था और ना ही वैक्सीनेशन के लिए आज की तरह कोई स्पेशल ड्राइव शुरू किया गया था। जबकि फरवरी 2020 में भी आईजीएमसी शिमला के अतिरिक्त मंडी और धर्मशाला में स्वाइन फ्लू के मरीज दाखिल थे। उस दौरान भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता में स्पेशल आईसीयू बनाने के निर्देश

दिये थे।

लेकिन कोविड – 19 के मामले में देश में 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन घोषित कर दिया गया जो कई चरणों में चला। इस लॉकडाउन के कारण अस्पतालों में ओपीडी और इन डोर दोनों सेवाएं बंद हो गई। उस समय अकेले आईजीएमसी का ओपीडी का 2018 का आंकड़ा 8 लाख रहा है। यदि उस समय अस्पताल में दाखिल मरीजों का 1% भी गंभीर रहा होगा तो उसका इलाज बंद होने पर उसकी क्या स्थिति रही होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कोविड कि वैक्सीन तो 16 जनवरी 2021 से शुरू हुई लेकिन इसका निर्माण लॉकडाउन से पहले ही हो चुका था यह तथ्य सामने आ चुका है। अप्रैल 2020 को तो एक डॉ. कुनाल शाह ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके इसके संभावित इलाज पर कुछ आशंकाएं उठाई थी। जिन्हें जस्टिस रमना की पीठ ने आईसीएमआर को भेज दिया था। इसी दौरान अजीम प्रेम जी के सहयोग से उनके एक नागपुर स्थित एनजीओ साथी की एक स्टडी भी सामने आई जिसमें खुलासा किया गया है कि फॉर्म कंपनियां अपनी दवाएं प्रमोट करने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाती हैं। फार्मा कंपनियों की इसी तरह की भूमिका का पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने भी अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है । आज भी सरकार के पास ऐसी कोई स्टडी नहीं है की लॉकडाउन से पूर्व जो लोग ओपीडी और इन डोर होकर इलाज करवा रहे थे उनमें से इलाज बंद होने पर कितने कोविड के संक्रमण का शिकार हुये और मर गये। आज यह सारे सवाल इसलिये प्रसांगिक हो जाते हैं की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर यह कहां है की वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं वर्ण एच्छीक है। क्या इस शपथ पत्र के बाद कोई भी अधिकारी वैक्सीनेशन को लेकर कोई लिखित आदेश करेगा। आज जो स्टैंड वैक्सीनेशन को लेकर लिया गया है पूर्व में ऐसा ही स्टैंड आरोग्य सेतु एप को लेकर भी रहा है।

अब जब केंद्र सरकार ने शपथ पत्र देकर यह कहा कि वैक्सीनेशन ऐच्छिक है और इसे वैधानिक अनिवार्यता नहीं बनाया गया है तब यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है। इसको लेकर जो अन्य मास्क आदि को लेकर जो निर्देश जारी किये गये हैं और उनकी अनुपालना न किये जाने पर जो जुर्माना आदि लगाया जा रहा है उसका वैधानिक आधार क्या है। क्योंकि किसी भी बीमारी का सबसे बड़ा पक्ष उसकी दवाई होता है। यह वैक्सीनेशन इस बीमारी में दी जाने वाली कोई दवाई नहीं है इससे केवल इसके संक्रमण से कुछ समय के लिए बचा जा सकता है। यह भी नहीं है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद आदमी कोविड का संक्रमित नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग इस बीमारी को महामारी की संज्ञा देने का विरोध करते हुये इसे सामान्य बीमारियों की तरह ही लेने की राय दे रहे थे वह शायद सही थे। 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाकर जिस तरह की बंदीशें लगा दी गई थी और उनसे जिस तरह का नकारात्मक प्रभाव देश की आर्थिकी और अन्य क्षेत्रों पर पड़ा है उस सब पर सरकार के इस शपथ पत्र के बाद देर सवेर जो सवाल और चर्चाएं उठाएंगे उनका अंतिम परिणाम कहीं आपातकाल में लाये गये नसबंदी अभियान जैसा ही ना हो इसकी संभावनाएं बनती जा रही है।

क्या चार शून्य का

....पृष्ठ 1 का शेष

है। यह सब प्रदेश की जनता के सामने घटा है और वह याद रखे हुए हैं। आज जब नड्डा काम की परख की बात करते हैं तो यह सही है। क्योंकि हर सरकार यही दावा करती है कि उसने बहुत काम किये हैं। अपने कामों के लिये सर्वश्रेष्ठता के पुरस्कार भी सरकारें प्राप्त कर लेती हैं। जो सर्वश्रेष्ठता आज जयराम सरकार को मिल रही है पूर्व में वही सर्वश्रेष्ठता के पुरस्कार प्रोफेसर धूमल और फिर वीरभद्र की सरकारों को भी मिल चुके हैं। लेकिन इन पुरस्कारों की जमीनी हकीकत की भुक्तभोगी रही जनता ने उनको रिपीट नहीं करवाया। उनके वक्त में ऐसे उपचुनाव नहीं आये थे अन्यथा वह अपना संदेश पहले ही दे देती। आज जयराम के वक्त में आये यह उपचुनाव और उनके परिणाम नड्डा के आग्रह पर पूरे उतरते हैं। जनता ने अपना फैसला एक तरह से सुना दिया है। इस फैसले को पढ़ना या इस पर आंखें बंद कर लेना यह राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना इम्तहान होगा।

क्योंकि जब वह स्ट्रांग लीडर तलाशने की बात करते हैं तब वह यह तलाश कार्यकर्ताओं के जिम्मे लगाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। पुलिस कर्मियों के परिजन अपने नेता को मिलने आये थे उसके सामने अपनी बात रखने आये थे यदि अपने नेता को मिलने के लिये भी उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हो और नड्डा इस पर भी खामोश रहे तो इसी से भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है

क्या प्रदेश कांग्रेस में

....पृष्ठ 1 का शेष

की जीत के श्रेय से कुलदीप राठौर के नाम को हटाना जनता में कोई अच्छा संदेश नहीं देगा। जब कुलदीप राठौर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 12 करोड़ के फर्जी बिल बनाकर हाईकमान को भेजने का आरोप लगाया था तब भी कांग्रेस के बड़े नेता उनके पक्ष में नहीं आये थे।

अभी प्रदेश कांग्रेस को वीरभद्र के समय में बने वीरभद्र ब्रिगेड के साथ जुड़े नेताओं कि संगठन में स्थापना के मुद्दे का भी सामना करना पड़ेगा। इसकी पहली जिम्मेदारी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह पर आयेगी। यह वीरभद्र की रणनीति रहती थी कि वह कई जगह समानांतर सत्ता केंद्र खड़े कर देते थे। लेकिन आज क्या प्रदेश कांग्रेस में इस सामर्थय का कोई नेता है शायद नहीं। फिर चारों उपचुनाव हारने से जो फजीहत भाजपा और जयराम सरकार की हुई है उससे उबरने के लिए भाजपा भी कुछ कदम तो उठायेगी ही। इसमें केंद्र से लेकर राज्यों तक भाजपा सरकारें जांच एजेंसियों का ही सबसे पहले उपयोग करती आयी है। बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में भाजपा कांग्रेस के खिलाफ सौंपे अपने आरोप पत्रों पर कुछ कार्रवाई करने का प्रयास करे। ऐसे में इस समय यदि कांग्रेस में मुख्यमंत्री की रेस अभी से शुरू हो जाती है तो वह संगठन और प्रदेश के हित में नहीं होगी। प्रदेश में पहले से ही स्वर्ण आयोग का भूत सक्रिय हो गया है और विक्रमादित्य सिंह तक इसकी छाया पड़ चुकी है। यहां यह स्मरण रखना होगा कि केंद्र ने क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख करने के बाद उस पर उठने वाले सवालों का रुख मोड़ने के लिए ही इस भूत को जगाया है। बल्कि आने वाले दिनों में भाजपा के बजाय कांग्रेस से लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी मैदान में होंगी। क्योंकि जिन कारपोरेट घरानों के इशारे पर कृषि कानून लाये गये थे अब इन कानूनों की वापसी के बाद इन घरानों का रुख टीएमसी की ओर मुड़ गया है। ममता बनर्जी और गौतम अडानी की मुलाकात से इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस को इन आने वाले खतरों के प्रति अभी से सावधान होना होगा।